

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के परामर्श से **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID)** को **कंपनी अधिनियम, 2013** के अंतर्गत एक “सार्वजनिक वित्तीय संस्थान” के रूप में अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य देश में अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देना है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनियों के नगिनन, ज़मिमेदारियों, नदिशकों और वधिटन को नयित्तरति करता है। इसने आंशकि रूप से **कंपनी अधिनियम, 1956 का स्थान लिया है।**
- यह अधिसूचना **बड़े पैमाने पर बुनयिादी अवसंरचनात्मक परयिोजनाओं** को वतितपोषति करने के लयि NaBFID की क्षमता को बढ़ाती है तथा राष्ट्रीय बुनयिादी अवसंरचना वतित पूरणाली को प्रभावी करती है।
- NaBFID की स्थापना वर्ष 2021 में **राष्ट्रीय अवसंरचना वतितपोषण और विकास बैंक अधिनियम (2021)** द्वारा भारत के पाँचवें अखलि **भारतीय वतित्तीय संस्थान (AIFI)** के रूप में की गई थी ताकि बॉन्ड और डेरविटवि बाज़ारों के विकास सहति दीर्घकालकि बुनयिादी अवसंरचना के वतितपोषण का समर्थन कयिा जा सके।
 - फरवरी 2024 तक एक वशिष **विकास वतित संस्थान (DFI)** के रूप में NaBFID ने पूरे देश में बुनयिादी अवसंरचना परयिोजनाओं के लयि 86,804 करोड़ रुपए से अधकि की मंजूरी दी है, जसिमें **50% मंजूरी 20 से 50 वर्षों की लंबी अवधि की है।** NaBFID ने मार्च 2026 तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधकि की मंजूरी देने की योचना बनाई है।
- अन्य चार AIFI:
 - **भारतीय नरियात-आयात बैंक (एकज़मि बैंक)**
 - **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबारड)**
 - **नेशनल हाउसगि बैंक (NHB)**
 - **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सडिबी)**

और पढ़ें: [राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक वधिषक, 2021](#)